दैनिक
बुद्ध का संदेश
हिन्दी समाचार पत्र
एक विश्वास....

वजन घटाने के लिए बेहद प्रभावी है ...8

सिद्धार्थनगर
रविवार, 24 अगस्त 2025
वर्ष: 12 अंक: 252 पृष्ठ: 8
आमंत्रण मूल्य 2/- रुपया

लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, रामपुर, रायबरेली, सिद्धार्थनगर से एक साथ प्रसारित।

सम्पादक : राजेश शर्मा

दैनिक बुद्ध का संदेश 8795951917, 9415163471 @budhakasandesh budhakasandeshnews@gmail.com www.budhakasandesh.com

उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

प्रियंका चतुर्वेदी की मांग, बंद हो भारत-पाकिस्तान मैच का लाइव टेलीकास्ट, अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर दुबई में 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच का सीधा प्रसारण रोकने की मांग की। मैच के आयोजन के फैसले की आलोचना करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि इस मुकाबले से बीसीसीआई को मिलने वाला पैसा सिर्फ खून का पैसा नहीं, बल्कि अपमान का पैसा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच आयोजित करने का केंद्र सरकार का फैसला पूरी तरह अस्वीकार्य है। ... मंत्रालय ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में दोनों टीमें खेल सकती हैं। अपने पत्र में चतुर्वेदी ने कहा कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच उन्हें पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने पत्र में लिखा कि आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का संदेश लेकर एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजा गया था, जिसका मैं भी हिस्सा थी, और (पाकिस्तान के) खिलाफ क्रिकेट मैच आयोजित करने का भारत सरकार का यह फैसला मुझे और मेरी अंतरात्मा को पूरी तरह अस्वीकार्य है। पहलगाम नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सरकार ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का भारत का संदेश पहुंचाने के लिए दुनिया भर में कई विभिन्न दलों के प्रतिनिधिमंडल भेजे थे। ... एशिया कप और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की भागीदारी पर जोर देने से निराश हैं।

नेशनल स्पेस डे पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
हमारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, शुभांशु शुक्ला की सफलता का भी किया जिक्र

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की कि भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन की सफलता का जिक्र करते हुए घोषणा की कि देश जल्द ही एक अंतरिक्ष यात्री पूल बनाएगा। उन्होंने युवाओं से इस पूल में शामिल होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत सेमी-क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी अभूतपूर्व तकनीकों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से भारत जल्द ही गगनयान की उड़ान भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में ... जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी तीन दिन पहले ही मेरी मुलाकात ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से हुई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गौरवान्वित किया। वह क्षण, वह अनुभूति जब उन्होंने मुझे तिरंगा दिखाया, शब्दों से परे है। उन्होंने आगे कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु के साथ अपनी चर्चा में मैंने नए भारत के युवाओं के असीम साहस और अनंत सपनों को देखा है। इन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम भारत का अंतरिक्ष यात्री पूल भी तैयार करने जा रहे हैं। आज अंतरिक्ष दिवस पर मैं अपने युवा मित्रों को भारत के सपनों को पंख देने के लिए इस अंतरिक्ष यात्री पूल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। मोदी ने कहा कि मैंने लाल किले से कहा था कि हमारा रास्ता रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता है। इसलिए पिछले 11 वर्षों में देश ने स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक अहम बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। आज स्पेस-टेक भारत में गवर्नेंस का भी हिस्सा बन रहा है। फसल बीमा योजना में उपग्रह आधारित आकलन हो, मछुआरों को उपग्रह से मिलने वाली जानकारी और सुरक्षा हो...।

उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी को मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष

आज तक ऐसा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं देखा...
जयशंकर ने ट्रंप की विदेश नीति की खोली पोल

नई दिल्ली। भारत और अमेरिकी रेड लाइन से ...

जनता को मिले त्वरित न्याय, तभी आएगा सुशासन
मुख्यमंत्री योगी ने दिया मंत्र

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ...

भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य को फिर लगा झटका, ईडी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

सीआरपीएफ नहीं, अभी भी दिल्ली पुलिस के पास है जिम्मेदारी सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ...

सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बनी हुई हैं

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार और गुणवत्ता सुनिश्चित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ...

पाकिस्तानी विमानों की एयर स्पेस में नो एंट्री, 23 सितंबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली। भारत ने एक बार फिर ...

पहलगाम के बाद के उपायों और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा

हम किसी से नहीं डरते, सच बोलते हैं...
खुद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले तेजस्वी यादव

पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ...

डबल इंजन सरकार में बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए कर रही कार्य : विधायक विनय वर्मा

दैनिक बुद्ध का संदेश
शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर। लोकप्रिय विधायक शोहरतगढ़ विनय वर्मा ने शुक्रवार को विकास खण्ड शोहरतगढ़ के ग्राम पंचायत कोटिया (ठोठा-टेकरिया, सिहोरवा, कुरहा, औरवाह व करमा) में पंचायत जनजागरण केन्द्र व प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान गांव की लोगों ने फूल-माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया। विधायक विनय वर्मा ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में बिना भेदभाव के हर वर्ग के लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क व बिजली आदि पहले से काफी बेहतर है। स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिसका परिणाम है कि आज गांव स्वच्छ व सुन्दर दिखाई दे रहा। खुले में शौच से रोकने के लिए हर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। विधायक ने कहा कि मैं शोहरतगढ़ के हितों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे जीवन का हर क्षण और शरीर का हर कण शोहरतगढ़ के नाम है। मैं इन सभी प्रहारों के बावजूद शोहरतगढ़ का साथ कभी नहीं छोडूंगा। उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए अग्निपरीक्षाएं देनी पड़ती हैं और मैं इसकी लिए तैयार हूं। विधायक ने आगे कहा कि आज भारत का नाम दुनिया में शक्तिशाली देशों के रूप में उभरा है। गरीब मजदूर किसान शोषित ...

जोगिया में दिखे हिरण का झुंड

दैनिक बुद्ध का संदेश

अनियंत्रित होकर पलटा टेलर

दैनिक बुद्ध का संदेश

पौराणिक भद्रेश्वरनाथ मंदिर के लिये होगा कारीडोर का निर्माण:दयाराम चौधरी

दैनिक बुद्ध का संदेश

लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी को बिना किसी भेदभाव का मिल रहा है : विधायक विनय वर्मा

दैनिक बुद्ध का संदेश

डीएम ने विधायक को जिला मुख्यालय में किसी भी कार्यक्रम में ना बुलाते जाने पर जताया नाराजगी

दैनिक बुद्ध का संदेश

विश्व हिन्दू महासंघ प्रदेश मंत्री बने सुधीर सिंह का फूल मालाओं के साथ स्वागत

दैनिक बुद्ध का संदेश

राजन इण्टर नेशनल एकेडमी में शैक्षणिक गुणवत्ता पहली प्राथमिकता: शिखा चतुर्वेदी

दैनिक बुद्ध का संदेश

उपजिलाधिकारी व तहसीलदार की अध्यक्षता मे किया गया पीस कमेटी की मीटिंग

दैनिक बुद्ध का संदेश

डीआईजी ने परिक्षेत्र के अधिकारियो व कर्मचारियो के साथ की समीक्षा गोष्ठी

यूरिया खाद की किल्लत को लेकर 'आप' ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

दैनिक बुद्ध का संदेश

खाद की कीमतों में मनमानी से रिटेलर विक्रेता हुए नाराज, डीएम को सौंपा ज्ञापन

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। खुदरा रिटेलर (फुटकर विक्रेता) [illegible]

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ने आचार्यों का नहीं किया पदोन्नति, आक्रोश

दैनिक बुद्ध का संदेश

कपिलवस्तु/सिद्धार्थनगर। [illegible]

चोरों का तांडव जारी, दस दिन में दो गांवों में लाखों की हुई चोरी, चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर

दैनिक बुद्ध का संदेश

[illegible]

यूरिया खाद लेने पहुंचे किसानों पर चला पुलिस का हुआ लाठीचार्ज

दैनिक बुद्ध का संदेश

शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर। [illegible]

मदरसे की बस से घायल युवक की 24वें दिन हुई मौत

दैनिक बुद्ध का संदेश

[illegible]

सिविवि में नौकरी के नाम पर ठगी, न्याय के लिए आवेदिका ने पीएम से लगाई गुहार

दैनिक बुद्ध का संदेश

कपिलवस्तु/सिद्धार्थनगर। [illegible]

गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मनमानी से बच्चों का भविष्य खतरे में

विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर खड़े हो रहे प्रश्न

दैनिक बुद्ध का संदेश/

[illegible]

खेसरहा पुलिस पर लापरवाही का आरोप, एसपी से शिकायत

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। [illegible]

बैदौला चौराहे पर लगा वाटर कूलर कई महीनों से खराब

दैनिक बुद्ध का संदेश

डुमरियागंज/सिद्धार्थनगर। [illegible]

सम्पादकीय

यही वजह है कि एक बहुचर्चित मेडिकल पत्रिका ने चेताया है कि भारत में 2050 तक पैंतालीस करोड़ युवा मोटापे की चपेट में आ सकते हैं। इस समस्या का एक पहलू यह भी है कि सोशल मीडिया पर मोटापा कम करने के नीम-हकीमी नुस्खों की भरमार आई है। हर दूसरा आदमी मोटापा कम ...

बदली खानपान की आदतों से बढ़ी मुसीबत

देश में जिस तेजी से मोटापा और उससे जनित रोगों का दायरा बढ़ा है, उससे यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात जैसी स्थिति बनती जा रही है। जिससे मोटापा जनित गैर संक्रामक रोगों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। एक हालिया अध्ययन में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुलासा किया है कि साल 2023 तक भारत की शहरी आबादी में मोटापे की दर 20 से 25 फीसदी तक जा पहुंची है। जबकि वर्ष 1990 में देश यह दर महज नौ से दस प्रतिशत ही थी। चिंता की बात यह है कि महज तीन दशक में मोटापा बढ़ने की यह दर दो गुना हो चुकी है। यही वजह है कि शहरों में आजकल हर दूसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार दिखाई देता है। दरअसल, देश में जैसे-जैसे आर्थिक समृद्धि आई तो हमारी खान-पान की आदतों में बदलाव आया है। हमारे भोजन में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, अधिक शुगर वाले पेय पदार्थ और मुख्यतः में जंक फूड का उपयोग तेजी से बढ़ा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि खाद्य तेलों का उपयोग भी बहुत तेज गति से बढ़ा है। आर्थिक विकास से समृद्धि आई तो हमारा खानपान समृद्ध हुआ, लेकिन वहीं शारीरिक निष्क्रियता भी बढ़ी है। दरअसल, खाद्य तेलों का बेतहाशा उपयोग भी मोटापे की वजह बना है। देश में नब्बे के दशक में जहां प्रति व्यक्ति तेल की औसतन खपत साढ़े तीन से चार लीटर थी, जो अब करीब बीस लीटर सालाना हो गई है। यानी चिंताजनक स्थिति तथा खतरनाक पांच गुना हो गई है। अब मोटापे की समस्या से शहर ही नहीं, ग्रामीण जीवन भी प्रभावित हो रहा है। बीती सदी में ऐसा देखने में नहीं आता था। दरअसल, इस सदी की शुरुआत में आई आर्थिक समृद्धि ने न केवल हमारी खानपान की आदतें बदलीं, बल्कि वाहनों के अधिक उपयोग व आरामदायक जीवनशैली ने हमारी शारीरिक सक्रियता भी कम कर दी। जो मोटापे की एक बड़ी वजह बना। देश में मोटापे की समस्या किस हद तक बढ़ चुकी है और इससे गैर संक्रामक रोग कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कई सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने देश में पनपते मोटापे पर गंभीर चिंता जताई। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भी वे मोटापे से मुक्त जीवन के लिये आदत स्वभाव में बदलाव की बात कह चुके हैं। उन्होंने खाद्य तेलों के उपयोग में कमी लाने की भी बात कही। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह चुका है कि फास्ट-फूड तथा एनर्जी से अधिक खाद्य पेय का सेवन मोटापे, उच्च रक्तचाप, दिल के रोग और डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि खानपान की आदतों में सुधार और शारीरिक सक्रियता बढ़ाने से हम मोटापा कम कर सकते हैं। नियमित व्यायाम व योग-प्राणायाम इसमें खासे मददगार हैं। यहां सवाल हमारी जीवन शैली में आये बदलावों का भी है। जिसमें हम देर रात को अधिक गरिष्ठ भोजन करते हैं। देर से सोना और देर से जागना अब आम बात हो चुकी है। तेजी से होते शहरीकरण, दफ्तरों में देर तक काम करने, शारीरिक सक्रियता में कमी तथा देर रात तक सोशल मीडिया में उलझे रहने से भी नींद की कमी ने जीवन में तनाव को बढ़ाया है। यह तनाव हमारी खानपान की आदतों को बुरी तरह प्रभावित करके मोटापे को बढ़ाता है। यही वजह है कि एक बहुचर्चित मेडिकल पत्रिका ने चेताया है कि भारत में 2050 तक पैंतालीस करोड़ युवा मोटापे की चपेट में आ सकते हैं। इस समस्या का एक पहलू यह भी है कि सोशल मीडिया पर मोटापा कम करने के नीम-हकीमी नुस्खों की भरमार आई है। हर दूसरा आदमी मोटापा कम करने के तरीके बताता नजर आता है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से सब प्रामाणिक नहीं हैं। लेकिन फिर भी लोग आंख मूंदकर उन पर विश्वास करने लगते हैं। कुछ लोग बिना जानकारी खाना-पान त्याग वजन घटाने का उपक्रम करके अपने शरीर से खिलवाड़ करने लगते हैं। वजन घटाने में सावधानी की सही प्रक्रिया भी होती है। जल्दबाजी के चक्कर में कई लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं।

साहित्यकार प्रो हरिराम त्रिपाठी का सड़क दुर्घटना में निधन

सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक के वर्तमान कुलपति प्रो. हरिराम त्रिपाठी जी का सड़क दुर्घटना में असामयिक देहावसान हो गया है। प्रो. हरिराम त्रिपाठी (जन्म 1 अगस्त 1966, कुशीनगर), एक प्रतिष्ठित विद्वान थे, जो न्याय व्याकरण, भारतीय दर्शन, सांख्ययोग, अद्वैत वेदांत, और न्याय में विशेषज्ञता रखते थे। वे पहले वाराणसी के सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे और 2022 में कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए थे। मऊ-गोरखपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा कविकुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय के कुलपति हरिराम त्रिपाठी और पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया है कि मऊ-गोरखपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात एक दुखद सड़क हादसे में महाराष्ट्र के कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक (नागपुर) के कुलपति प्रो. हरिराम त्रिपाठी और उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा दोहरीघाट थाना क्षेत्र के [illegible] गांव के पास हुआ, जब उनकी तेज रफ्तार इनोवा कार एक खड़े ट्रक (डंपर) से जा टकराई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे शिक्षा जगत और उनके गृह जनपद कुशीनगर में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रो. हरिराम त्रिपाठी अपनी पत्नी के साथ वाराणसी से अपने गृह जनपद कुशीनगर जा रहे थे। रात करीब [illegible] बजे उनकी इनोवा कार ने हाईवे पर खड़े एक डंपर में जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीयों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दंपति को बचने का कोई मौका नहीं मिला। यह हादसा सड़क सुरक्षा और हाईवे पर खड़े वाहनों की समस्या पर सवाल उठाता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि हाईवे पर सुरक्षा उपायों को और सख्त किया जाए। ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।

लेखक विनय कांत मिश्र / दैनिक बुद्ध का संदेश

मानसून के लिए नई रणनीति बनाने की जरूरत

डॉप्लर रडार और स्वचालित मौसम स्टेशनों के नेटवर्क में विस्तार, जैसा कि मिशन मौसम के तहत परिकल्पित है, स्थानीय पूर्वानुमानों में सुधार ला सकता है। आईएमडी का भारत फोरकास्टिंग सिस्टम एक सही कदम है। जलवायु परिवर्तन ने मानसून के पैटर्न में बदलाव किया है और भारी बारिश की घटनाओं को बढ़ाया है, भारत की नीतियों, योजनाओं और डेटा प्रणालियों को इसके साथ तालमेल बनाना चाहिए...

जलवायु परिवर्तन ने मानसून के पैटर्न में बदलाव किया है और भारी बारिश की घटनाओं को बढ़ाया है, भारत की नीतियों, योजनाओं और डेटा प्रणालियों को इसके साथ तालमेल बनाना चाहिए। जलवायु विनियमित करने का अर्थ है कि आसमान अभी हमें जो बता रहा है, उसके अनुरूप खुद को ढालना है, न कि पहले से क्या करते आ रहे थे उसे देखना। दक्षिण-पश्चिम मानसून को भारत की जान और खाद्य तंत्र की रीढ़ कहा जाता है, जो जून से सितंबर के बीच देश में लगभग तीन-चौथाई वार्षिक वर्षा लाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान लगाया है। लेकिन इसमें सिर्फ यही मायने नहीं रखता है कि कुल कितनी बारिश हुई, बल्कि यह भी अहम है कि कब, कहां और कैसी बारिश हुई है। जलवायु परिवर्तन ने बारिश के पैटर्न को अनिश्चित बनाया है। वर्ष 2025 में अब तक का मानसून पूरे देश में भारी और चरम वर्षा की विभिन्न घटनाओं से भरा हुआ है। जुलाई में अच्छी बारिश ने खरीफ की बुआई को तेज कर दिया, माह के अंत तक 70.3 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 4.1 प्रतिशत अधिक रही। दूसरी तरफ पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों को अत्यधिक बारिश से जूझना पड़ा है, जिससे अचानक बाढ़ की घटनाएं सामने आई हैं। सीईईडब्ल्यू के एक अध्ययन में पाया गया कि 55 प्रतिशत तहसीलों में जून से सितंबर के बीच कुल बारिश बढ़ी है। खास बात यह कि यह बढ़ोतरी भारी बारिश वाले दिनों की संख्या बढ़ने से हुई है। नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, पिछले सात दशकों में प्रति घंटे बारिश के पैटर्न की पड़ताल में सामने आया है कि मध्य भारत में कम समय में भारी बारिश और उत्तर-पश्चिमी तट पर लंबे समय तक भारी बारिश की घटनाएं अधिक संख्या में हो रही हैं। पिछले दो दशकों में भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में उल्लेखनीय रूप से निवेश किया है और देश व राज्यों के स्तर पर जलवायु कार्य योजनाएं शुरू की हैं। फिर भी जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है और बारिश में तेजी से अनिश्चितता आ रही है, इसका सामना करने की क्षमता विकसित करने में ये तीन कदम सहायक हो सकते हैं। पहला, शहरों को बीते कल के औसत के लिए नहीं, अधिक बाढ़ की घटनाओं के लिए योजना बनानी चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों को बाढ़ का सामना करने के लिए बनाई जाने वाली योजना का दोबारा मूल्यांकन करना चाहिए। पारंपरिक बाढ़ प्रबंधन इस ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करता है कि कितनी बार और कितनी भारी बारिश हुई है, जिसे तूफानी घटनाओं की तीव्रता-अवधि-आवृत्ति कहा जाता है। लेकिन अब यह विश्वसनीय नहीं रह गया है, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका मतलब लंबे समय तक सूखा रहना और फिर बहुत तेज बारिश होना है। महाराष्ट्र के ठाणे में पुराने जल-निकासी तंत्र (ड्रेनेज सिस्टम) को एक घंटे की अधिकतम बारिश को संभालने के लिए नहीं बनाया गया था, जबकि बीते एक दशक में औसतन बारिश 64 मिमी प्रति घंटा रही है। (शहरों के लिए, 100 मिमी प्रति घंटा बारिश को बादल फटना माना जाता है।) इसे समझते हुए, ठाणे नगर निगम ने अपने बाढ़ के खतरे के अनुमानों में बदलाव किया है और अब अपने तूफानी जल-निकासी वाले नालों (स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स) को फिर से बना रहा है। भारत के अन्य शहरों को भी ऐसा करना चाहिए। दूसरा, किसानों को अपने फसल कैलेंडर को अपडेट करने की जरूरत है। बारिश के बदलते पैटर्न के साथ, राज्यों और केंद्रीय कृषि विभागों और मौसम विज्ञान एजेंसियों को नियमित फसल कैलेंडर को अपडेट करना चाहिए, खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहां वर्षा आधारित खेती होती है। अध्ययन से पता चलता है कि अनियमित मानसूनी बारिश विशेष रूप से धान, मक्का और दालों जैसी प्रमुख फसलों की बुआई और कटाई के मौसम को बदल रही है। यहीं, भारत की आधी से अधिक तहसीलों में अक्टूबर महीने में बारिश में वृद्धि देखी गई, जिससे फसलों की कटाई प्रभावित होती है। [illegible] रूप से फसल का नुकसान होने पर राहत भुगतान की शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक अधिक दूरदर्शी दृष्टिकोण में फसल चक्रों को नए सिरे से व्यवस्थित करना, जलवायु-अनुकूल बीज उपलब्ध कराना, और किसानों की सुरक्षा के लिए व्यावहारिक योजनाओं का निर्माण शामिल होना चाहिए। तीन, स्थानीय स्तर पर मौसम के अधिक सूक्ष्म आंकड़ों को जुटाने में निवेश करें और उनकी उपयोग की क्षमता बढ़ाएं। स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रतिक्रिया देने और इन पूर्वानुमानों और अधिक उपयोगी बनाने के साथ मानसून पूर्व-अवधारणों को दुरुस्त बनाने के लिए हमें और अधिक सूक्ष्म या स्थानीय आंकड़ों की जरूरत है।

नियमों और दिशा-निर्देशों का प्रभाव कानून के बराबर ही होता है और उन्हें हमेशा कानूनी तरीके से ही बनाया जाना चाहिए, आपराधिक मामलों में तो ऐसा और भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि इनका व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से, हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा-निर्देशों को अन्य हितधारकों के साथ बैठकर पुन: कानूनी ...

कसौटी पर हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा-निर्देश

हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित हालिया सामुदायिक सेवा दिशा-निर्देश भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 (एफ) और संविधान के अनुच्छेद 162 को एक साथ मिलाकर बनाए गए हैं। लेकिन इन केंद्रीय कानूनों में राज्यों को सामुदायिक सेवा दंड संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाला प्रावधान नहीं। इस दस्तावेज की कानूनी वैधता पर सवाल उठ सकता है। दिल्ली के बाद, हरियाणा सरकार ने भी 18 अगस्त, 2025 को सामुदायिक सेवा दिशा-निर्देश (एचसीएसजी) अधिसूचित कर दिए हैं। दोनों ही दिशा-निर्देशों के आरम्भिक वाक्य में कहा गया है कि ये दिशा-निर्देश भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 4 (एफ) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत बनाए गए हैं, जबकि इनमें से कोई भी प्रावधान राज्य सरकार को ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं देता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 (एफ) अपराधियों को दी जाने वाली सजा के प्रकार उल्लिखित करती है, तथा संविधान के अनुच्छेद 162 में राज्यों की कार्यकारी शक्तियों की सीमा का प्रावधान है। किसी भी विषय पर नियम अथवा दिशा-निर्देश जारी करने की शक्तियां सम्बन्धित कानून में स्पष्ट रूप से लिखित प्रावधान द्वारा कार्यपालिका को प्रदान की जाती हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) दोनों ही केंद्रीय कानून हैं और राज्य सरकारें सामुदायिक सेवा दंड (सीएसएस) के निष्पादन पर प्रत्यायोजित (डेलिगेटेड) कानून का सहारा तभी ले सकती हैं जब इन कानूनों में इसका स्पष्ट प्रावधान हो। हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा-निर्देशों को जायज ठहराने के लिए राज्यों को इससे संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाला कोई प्रावधान नहीं है, जिससे पूरी प्रक्रिया बिना कानूनी आधार की गतिविधि मात्र बनकर रह जाती है। वास्तव में, बीएनएसएस का मसौदा तैयार करते समय विधान मंडल अनभिज्ञता से अध्याय 34 में सीएसएस के निष्पादन से सम्बन्धित उचित प्रावधान जोड़ना भूल गए, जैसा कि पहले से ही कुछ दंड कारावास अथवा जुर्माना लगाने की सजा के निष्पादन के लिए किया गया है। यह त्रुटि शायद जल्दबाजी के कारण हुई क्योंकि सामुदायिक सेवा को बीएनएस में पहली बार दंड की सूची में शामिल किया गया था। परिणामस्वरूप, सीएसएस के निष्पादन पर नियम बनाने की शक्ति भी गैर-निर्दिष्ट रह गई। आदर्श रूप से, हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा-निर्देश तैयार करने से पूर्व राज्य सरकार को केंद्र सरकार के समक्ष बीएनएसएस में धारा 480 के बाद एक नए उप-शीर्षक 'सामुदायिक सेवा के अन्तर्गत' एक नई धारा शामिल करने का प्रस्ताव भेजना चाहिए था। ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों के अभाव में हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा-निर्देश और दिल्ली के दिशा-निर्देश, राज्य-कार्यपालिका की विधायी अक्षमता का शिकार हैं और दोनों ही दस्तावेज गैर-कानूनी हैं। यह आश्चर्यजनक है कि दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करने से पहले इतनी बड़ी गलती कैसे उजागर नहीं हो सकी। हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा-निर्देश कई अन्य प्रकार से भी संदिग्ध प्रतीत होते हैं। सबसे पहले, दिशा-निर्देश यह वर्णित करते हैं कि वे उन मामलों पर भी लागू होंगे जहां बाल-न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे एक्ट) की धारा 18(1) (सी) के अन्तर्गत बच्चों को सामुदायिक सेवा करने के आदेश पारित किए जाते हैं। [illegible] अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए यह उचित नहीं है कि गृह विभाग इसकी कार्यान्वयन पर दिशा-निर्देश जारी करे। दूसरा, दिशा-निर्देशों के पैरा 7 में अदालतों के लिए एक सुझाव दिया गया है कि सीएसएस आदेश पर पहुंचने से पूर्व [illegible], जबकि बीएनएसएस में छोटी-मोटी चोरी के मामलों को छोड़कर ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है। इससे यह प्रासंगिक प्रश्न भी उठता है कि क्या कार्यपालिका दिशा-निर्देश में ऐसी कोई अतिरिक्त शर्त निर्धारित कर सकती है जो मूल अधिनियम में नहीं है? क्या कार्यपालिका को यह निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि अदालतों को अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तीसरा, पहली बार अपराधियों और बार-बार अपराधियों के लिए सीएसएस पर दिशा-निर्देशों को एक ही दस्तावेज में शामिल करना नीतिगत रूप से उचित नहीं होता है। किशोरों के लिए सामुदायिक कार्य पर दिशा-निर्देशों को बच्चों और किशोरों से सम्बन्धित श्रम कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। चौथा, सीएसएस एक सजा है जो न केवल दोषी के निजी आपराधिक रिकॉर्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, बल्कि उसकी भविष्य में होने वाली किसी भी [illegible] पर भी असर डालती है। इसलिए दिशा-निर्देशों में सामुदायिक सजा के निष्पादन [illegible] किया जाएगा। हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा-निर्देशों के पैरा 6 के अन्तर्गत, सीएसएस के प्रशासनिक निष्पादन के लिए उपयुक्त समिति और निगरानी तन्त्र निर्धारित करने का कर्तव्य [illegible] पर डाला गया है। कार्यपालिका को ऐसे निर्देश देने से बचना चाहिए। ऐसे निर्देश केवल उच्च न्यायालय के नियम और आदेश के अन्तर्गत ही जारी किए जा सकते हैं। तथा, दिशा-निर्देशों में 'नोडल अधिकारी', [illegible] और 'सक्षम प्राधिकारी' आदि जैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है जो भारत में [illegible] न्याय-व्यवस्था के लिए नई है। चूंकि सामुदायिक सेवा एक नूतन दंड है इसलिए इसके निष्पादन के मामले में प्रयुक्त शब्दावली अन्य दंडों के समान ही होनी चाहिए।

जीएसटी कटौती से Car, SUV, TV, Mobile, AC सस्ता होने के इंतजार में हैं ग्राहक, त्योहारों से पहले बाजार दिख रहे सूने, दुकानदार चिंतित

[illegible]

[illegible]

मस्क ने जिसे सांप बताया, उसे भारत भेज ट्रंप मोदी सरकार को देना चाह रहे ये संदेश

[illegible]

[illegible]

MAGA में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

[illegible]

अनिल अंबानी की कम नहीं हो रही मुश्किलें, ईडी के बाद अब सीबीआई ने मारा छापा

[illegible]

[illegible]

पटना में टैंकर और टेम्पो की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल

[illegible]

मोदी के चीन जाने से पहले जिनपिंग का बड़ा धोखा, एक्शन में भारत

[illegible]

[illegible]

शेख हसीना की खबर दिखाई तो...मीडिया पर सेंसरशिप लगाने वाली है बांग्लादेश की युनूस सरकार?

[illegible]

[illegible]

आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो...रूसी तेल खरीद पर ट्रंप को जयशंकर जैसा जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा

[illegible]

[illegible]

जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अभिनव पहल

कक्षा 08 उत्तीर्ण ड्राप आउट बच्चों को विद्यालयों में मिलेगा प्रवेश

दैनिक बुद्ध का सन्देश

बहराइच। परिषदीय विद्यालयों से कक्षा 08 उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का उच्च कक्षाओं में प्रवेश के लिए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा अभिनव प्रयास किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि ड्राप आउट बच्चों के सर्वे के दौरान बच्चों की पारिवारिक स्थिति इत्यादि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें ताकि अध्ययन के कारण आगे की शिक्षा ग्रहण करने में [illegible]

[illegible]

पुण्य तिथि पर याद किये गये पूर्व सांसद कल्पनाथ सोनकर

दैनिक बुद्ध का संदेश

बस्ती। पूर्व सांसद कल्पनाथ सोनकर की उनकी 15 वीं पुण्य तिथि पर शनिवार को उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। [illegible]

आगामी त्यौहार कजरीतीज को लेकर सरजू घाट (भग्गड़वा बाजार) का किया गया निरीक्षण

दैनिक बुद्ध का सन्देश

बहराइच। आगामी त्यौहार कजरी तीज पर्व को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक नगर [illegible]

[illegible]

33176 बैग यूरिया जनपद बहराइच को हुई प्राप्त

दैनिक बुद्ध का सन्देश

बहराइच 23 अगस्त। जिला कृषि अधिकारी डॉ सूबेदार यादव ने बताया कि जनपद बहराइच को यूरिया की 33176 बोरी [illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग की "प्रतिनिधि चिंतन कार्यशाला" में अधिवक्ताओं ने लिया न्याय दिलाने का संकल्प

लखनऊ। [illegible]

लखनऊ में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की चिंतन बैठक: देश की शिक्षा को नया विकल्प देने का प्रयास

[illegible]

महसी में सम्पन्न हुई ब्लॉक बाल संरक्षण समिति की बैठक

दैनिक बुद्ध का सन्देश

बहराइच। [illegible]

राष्ट्रीय लोक अदालत में आए मामलों का कराएं निस्तारणरू सचिव

देवरिया। जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष [illegible] सिंह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जनपद न्यायालय के वीडियो कांफ्रेंसिंग भवन में सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ प्री-ट्रायल बैठक हुई। प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने निर्देश दिया कि सभी विभाग मामलों को चिन्हित कर सूचना दें और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में मामलों का निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि दिनांक 10 से 12 सितंबर को न्यायालय में लघु वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वादकारियों से अपील है कि विशेष लोक अदालत में अपने सुलहनीय मामलों को न्यायालय में नियत कराकर अपने वादों का निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए प्रचार-प्रसार तथा अपने विभाग से संबंधित जो भी मामले हैं [illegible] चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराएं और अब तक चिन्हित मामलों की संख्या से अवगत कराएं।

रोजगार मेला 25 को

देवरिया। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सेवायोजन कार्यालय एवं मॉडल कैरियर सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में 25 अगस्त को सुबह 10 बजे से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। प्रभारी जिला सेवायोजन अधिकारी [illegible] ने बताया कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप मेले में सरकारी क्षेत्र की उत्तर प्रदेश परिवहन निगम देवरिया डिपो द्वारा संविदा चालकों की भर्ती की जाएगी।

भागलपुर में खतरे के निशान से नौ सेमी ऊपर ठहरी सरयू

देवरिया। सरयू नदी का उफान अब भी जारी है। हालांकि जलस्तर 12 घंटे से स्थिर है। जलस्तर स्थिर होने से तटवर्ती इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली है, मगर नदी अब भी खतरे के निशान से नौ सेमी ऊपर बह रही है। [illegible]

मोहन सेतु के पास कटान, थमा सरयू का जलस्तर

देवरिया। सरयू नदी खतरे के निशान 66.50 से 60 सेमी ऊपर [illegible] मीटर पर बह रही है। [illegible]

पंचायत चुनाव के लिए बीएलओ को मिला बैग

देवरिया। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। [illegible]

बायरल के बीच परेशान कर रहा हड्डियों का दर्द

महराजगंज। मौसम का उतार चढ़ाव [illegible]

प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल उद्योग एवं व्यवसाय में सुगमता ला रहा है

दैनिक बुद्ध का संदेश

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार समग्र सुधारों, डिजिटलीकरण एवं निवेशकों के अनुकूल नीतियों के माध्यम से व्यवसायों एवं निवेशों को सुगम बनाने में उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2022 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर्स तथा वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 में लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में एक्जम्प्लर्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। साथ ही राज्य को वर्ष 2021 के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान एवं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है जिससे यह भारत के सबसे सुरक्षित एवं निवेशक अनुकूल राज्यों में से एक के रूप में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश का समर्पित ऑनलाइन पोर्टल निवेश मित्र, सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम, 45 विभागों की सेवाओं को एकीकृत करता है, जो अनुमोदन, लाइसेंस एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु 525 से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह पोर्टल आवेदन प्रस्तुत करने एवं ट्रैकिंग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है जिससे विलम्ब एवं प्रशासनिक समस्याओं का न्यूनीकरण सुनिश्चित होता है। गत वर्ष में विभिन्न प्रोत्साहन, वि. उद्यान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं मनोरंजन, आबकारी, फार्मास्यूटिकल्स तथा भू-विज्ञान एवं खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनुमोदन सेवाएं भी निवेश मित्र पोर्टल में एकीकृत की गई हैं। निवेश मित्र पोर्टल देश के उन अग्रणी पोर्टलों में से एक है, जिन्हें नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम से एकीकृत किया गया है। निवेश मित्र में विभिन्न अन्य सेवाएं भी जोड़ी जा रही हैं तथा सभी प्रकार की एनओसी/अनापत्तियों को एक ही स्थान पर (वन-स्टॉप सॉल्यूशन) उपलब्ध कराने हेतु कार्य किया जा रहा है। उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदनों के 97 प्रतिशत से अधिक का निस्तारण किए जाने के साथ, निवेश मित्र पोर्टल वर्तमान में देश के सबसे कुशल सिंगल विंडो पोर्टलों में से एक बन गया है। व्यवसाय में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) प्रदेश में मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए निवेश मित्र पोर्टल में व्यापक प्रशासनिक सुधार लागू किए गए हैं जिनसे पारदर्शी एवं जवाबदेह, कुशल एवं प्रभावी ऑनलाइन अनुमोदन प्रणाली की स्थापना है। समस्त आवेदन अनिवार्य रूप से केवल निवेश मित्र के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं, भौतिक रूप से या विभाग के स्तर पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। संबंधित विभागों द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों एवं समस्त स्वीकृतियों से संबंधित पुनर्विचार आवेदन प्राप्त होने के बाद केवल 07 दिनों के भीतर एक बार की जा सकती है। अब तक निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 19 लाख से अधिक अनुमोदन डिजिटल रूप से निर्गत किए जा चुके हैं। पोर्टल पर उपलब्ध उपयोगकर्ता फीडबैक प्रणाली के अनुसार, 96 प्रतिशत उपयोगकर्ता निवेश मित्र से संतुष्ट हैं। नियामक अनुपालन भार (रेग्यूलेटरी कम्प्लायंस बर्डन) को कम करने की दिशा में किए गए कार्य सरकार इस पोर्टल को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने हेतु सक्रिय रूप से इसका पुनर्विकास कर रही है, जिसमें सिंगल विंडो अधिनियम 2024 को लागू करना भी सम्मिलित है। नियामक अनुपालन जटिलताओं को कम करने के प्रयासों के क्रम में, उत्तर प्रदेश में लगभग 65 विभागों में कुल 4,675 अनुपालन कम किए गए हैं। कुल 4,098 अनुपालनों को सुगम बनाया गया एवं डिजिटल रूप प्रदान किया गया है, जिनमें से 2,512 अनुपालनों को चौथी श्रेणी के अंतर्गत कम किया गया है एवं 1,586 अनुपालनों को पांचवीं श्रेणी के अंतर्गत कम किया गया है। इसके अतिरिक्त अब तक कुल 577 अनुपालनों को निरपराधीकरण (डिक्रिमिनलाइजेशन) श्रेणी के अंतर्गत लाया गया है। इसके साथ ही कुल 948 अधिनियम/नियम/विनियम आदि को समाप्त किया जा चुका है। अब उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए उ.प्र. दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के अंतर्गत पंजीकरण पर्याप्त है तथा ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए उ.प्र. दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत पंजीकरण के नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यदि दुकान में शून्य कर्मचारी हैं तो उ.प्र. दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। उद्यमों से संबंधित अनुपालनों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से निरपराधीकरण (डिक्रिमिनलाइजेशन) के लिए अग्निशमन विभाग, श्रम विभाग, नगरीय विकास विभाग व विधिक माप विज्ञान विभाग के कानूनों के अंतर्गत अपराधों की कम्पाउंडिंग कर दी गई है।

बीज विक्रेताओं का प्रशिक्षण 25 को मगुराही में

दैनिक बुद्ध का संदेश

सोनभद्र। जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद की समस्त बीज विक्रेताओं को 25 अगस्त 2025 को प्रातः 10.00 बजे से उप कृषि निदेशक, मगुराही सोनभद्र स्थित सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण में बीज की बिक्री, स्टॉक इत्यादि के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा विकसित किये गया साथी पोर्टल के फेज-2 के क्रियान्वयन हेतु जानकारी दिया जाना है। उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त बीज विक्रेताओं को निर्देशित/सूचित किया जाता है कि 25 अगस्त 2025 को प्रातः 10.00 बजे से उप कृषि निदेशक, मगुराही, स्थित सभागार में समयान्तर्गत उपस्थित होकर ऑन-लाइन माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

दैनिक बुद्ध का संदेश

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना बीजपुर पुलिस द्वारा थाना बीजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-70/25 धारा 87, 137(2), 65(1) बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मोनू कहार पुत्र जोखन कहार निवासी ग्राम बभनी थाना बभनी जनपद सिंगरौली म0प्र0 को आज दिनांक-23.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर बस पुल सिंगरौली से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

राशनकार्ड में जोड़ी गई यूनिट का खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व ई-केवाईसी कराना होगा अनिवार्य-जिला पूर्ति अधिकारी

दैनिक बुद्ध का संदेश

सोनभद्र। जिला पूर्ति अधिकारी पुरु गुप्ता ने अवगत कराया है कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ के निर्देशानुसार ऐसे सभी राशनकार्ड के लाभार्थियों को (यूनिट) जिनकी ई-केवाईसी कराये जाने का कार्य अवशेष है, उनको लाभित होने वाले खाद्यान्न का वितरण अंतिम माह तक नियंत्रित करते हुए उनके ई-केवाईसी कराये जाने हेतु एस0एम0एस0 के माध्यम से रिमाइन्डर प्रेषित कर अवगत कराया जाय कि इन तीन माहों में प्रत्येक दशा में ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उनकी यूनिट उनके राशनकार्ड से निरस्त कर दी जायेगी, जिन राशन कार्ड लाभार्थियों द्वारा दी गई समयावधि में ई-केवाईसी करा ली जायेगी, वे अंतिम माह से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अर्ह होंगे। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि नये राशनकार्ड से सम्बन्धित सभी सदस्यों (यूनिट) को अथवा प्रचलित राशनकार्ड में जोड़ी गई यूनिट को खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य है।

जनपद के समस्त थानों पर आयोजित किया गया थाना समाधान दिवस

दैनिक बुद्ध का संदेश

सोनभद्र। जनपद के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा थाना चोपन पर आयोजित समाधान दिवस के अवसर फरियादियों

की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया साथ ही निर्देशित किया गया कि जमीन सम्बन्धित सभी प्रकरणों में पुलिस व राजस्व की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकरण का निस्तारण किया जाए, जिससे फरियादियों को अलग-अलग भटकना न पड़े व प्रकरणों का त्वरित व न्याय पूर्ण निस्तारण हो सके। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री कालू सिंह द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर, क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना चोपन पर, क्षेत्राधिकारी ओबरा द्वारा थाना ओबरा पर, क्षेत्राधिकारी पिपरी द्वारा थाना पिपरी पर तथा क्षेत्राधिकारी दुद्धी द्वारा थाना दुद्धी पर व थाना प्रभारियों द्वारा अपने थानों पर थाना समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की समस्याओं को सुनकर कुछ का मौके पर निस्तारण किया गया तथा कुछ के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

श्रीराम चरित मानस मन्दिर समिति ने कराया विशाल भंडारे का आयोजन

दैनिक बुद्ध का संदेश

ओबरा/सोनभद्र। स्थानीय राम मंदिर प्रांगण में भगवान श्रीकृष्ण की छठी के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन श्रीराम चरित मानस मंदिर समिति ने शुक्रवार देर शाम कराया। इस दौरान समिति की महिला मण्डल की अध्यक्षा सुमन उर्फ मनोरमा सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा भगवान के अनेकों अनेक भजनों को गायन कर नाचा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मनोहारी गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय रहा। छठी के इस पावन अवसर पर नगरवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल, समिति के अध्यक्ष ईश्वरी नारायण सिंह, सचिव श्रीप्रकाश तिवारी, संरक्षक मण्डल में प्रमुख रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता अभय चन्द्र पाण्डेय, सतीश कुमार चौबे, गिरीश नारायण सिंह, आनन्द शर्मा, मुरलीधर शर्मा, अवधेश सिंह, पूर्व चेयरमैन प्रभावती देवी, रमेश सिंह यादव, अरुण भारद्वाज, रचना सिंह, गीतांजलि चौबे, आचार्य मनमोहन शुक्ला, राजीव वैश्य, पुष्पराज पाण्डेय, ज्ञान शरण शुक्ला, सतीश पाण्डेय, रामनिवास तोमर, शिवमंगल जायसवाल, सुनीता पाण्डेय, कार्तिक तिवारी, निखिल मिश्रा, सतीश सिंह, सुरेन्द्र शर्मा, सतीश अग्रहरि, हेमलता जायसवाल, सुरेन्द्र सिंह पप्पू, पुष्पा दुबे, अनामिका सोनी, सुनीता दुबे, सुनील सिंह, रमेश चन्द्र शुक्ला, सरिता तिवारी, छोटेलाल मिश्रा, अमरेश यादव, मुकेश जायसवाल, सत्यम अमित गुप्ता, समीर भारती, अशोक अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, रामदेव मौर्य, शैलेश, सचिन तिवारी, सुनील सिंह, विनोद सिंह मुन्ना, सत्यम विकास सिंह, राजू साहनी, पवन यादव, अशोक यादव, अनुज त्रिपाठी, अभिषेक सेठ, अनीश सेठ, आर्यन सिंह, रवीश सिंह, प्रेम सागर, राजीव चौधरी, अनिकेत तिवारी, आदित्य त्रिपाठी इत्यादि लोग मौजूद रहे।

खाद वितरण में मूल्य से अधिक धनराशि लेने की शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्यवाही: जिलाधिकारी

दैनिक बुद्ध का संदेश

सोनभद्र। जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार, जनपद के विभिन्न तहसील क्षेत्र व बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों को बिक्री के लिए आवंटन के उपरान्त 24 घण्टे के अन्दर यूरिया खाद को पहुंचाने की स्थिति का औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिये। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति, मधुपुर तहसील राबर्ट्सगंज, बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति तथा बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति का आकस्मिक निरीक्षण किये। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सहकारी समिति पर आये किसानों को मौके पर ई-पास मशीन के माध्यम से खाद वितरण की स्थिति को देखा और संतोष व्यक्त किये। निरीक्षण के मौके पर उपस्थित किसानों से खाद वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त की, उन्होंने कहा

कि खाद वितरण सम्बन्धी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो, इसकी सूचना से अवगत कराये, जिससे कार्यवाही व विधिवत करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्टाक रजिस्टर से मिलान करते हुए खाद वितरण की स्थिति का जायजा लिये। उन्होंने किसान बन्धुओं को अवगत कराया करते हुए कहा कि सभी समितियों पर खाद समय से पहुंच जाये और किसानों को उपलब्ध हो जाये, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, किसान बन्धुओं को खाद की कोई कमी नहीं है, किसानों को धैर्य बनाये रखने की जरूरत है, सभी किसान बन्धुओं को खाद उपलब्ध करा दिया जायेगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने खाद वितरण व्यवस्था एवं मशीनों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0 को निर्देशित किया कि सहकारी समितियों का एकीकरण कराते हुए सहायक आयुक्त, सहायक निबन्धक से समन्वय स्थापित करते हुए नगद बिक्री केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करते तथा नगद उर्वरक वितरण समितियों/संघों को क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाये, जिससे किसी प्रकार की शिकायत की समस्या न होने पाये। जिलाधिकारी ने कहा कि खाद वितरण में किसी के द्वारा टैगिंग करने या मूल्य से अधिक धनराशि लेने की शिकायत मिलती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जायेगी, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जायेगी। इस मौके पर ए0आर0 को-आपरेटिव देवेन्द्र कुमार सिंह सहित समिति/संघों के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सहकारिता समितियों में डिजिटल क्रांति : एमपैक्स में क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली शुरू

लखनऊ। अगस्त 2025 प्रदेश सरकार सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने आज की एमपैक्स में क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया और सभी प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए ऑनलाइन भुगतान हेतु क्यूआर कोड जारी किए। राठौर ने कहा कि इस व्यवस्था से किसानों और उपभोक्ताओं को नगद लेन-देन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित व सुगम बनेगी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहकारिता के आधुनिकीकरण की संकल्पना की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। सहकारिता मंत्री ने बताया कि किसानों की लंबे समय से ऑनलाइन भुगतान की मांग थी। अब इस सुविधा से ओवर रेटिंग की समस्या खत्म होगी और खाद वितरण व्यवस्था और पारदर्शी बनेगी। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता है। एक बोरी यूरिया की कीमत 266.50 रुपये तथा डीएपी की कीमत 1,350 रुपये तय है। इस वर्ष सहकारी समितियों के माध्यम से 10 लाख 40 हजार मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह मात्रा 7 लाख 42 हजार मीट्रिक टन थी। यानी इस बार लगभग 40 प्रतिशत अधिक खाद वितरित हुई है। अब तक 35 लाख 58 हजार किसानों को सहकारी समितियों से खाद उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 6,851 प्राथमिक सहकारी समितियों अब उर्वरक वितरण का कार्य कर रही हैं, जबकि पहले केवल 1,400 समितियां ही सक्रिय थीं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देशन में बंद पड़ी समितियों को पुनर्जीवित किया गया है। प्रत्येक समिति को कार्य-व्यापार हेतु 10 लाख रुपये और भवन व गोदामों की मरम्मत के लिए भी 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। अब तक 980 समितियों की मरम्मत और 375 समितियों में नए गोदामों का निर्माण हो चुका है। राठौर ने बताया कि समितियों में आधुनिकीकरण के लिए कम्प्यूटर, प्रिंटर, एलईडी और बिजली न होने की स्थिति में 2 किलोवाट सोलर सिस्टम पैनल लगाए जा रहे हैं। समितियों की कार्यशील पूंजी को भी मजबूत किया गया है और कैश क्रेडिट लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की तैयारी है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे आवश्यकता के अनुसार ही खाद लें और अनावश्यक भंडारण न करें। कार्यक्रम में वी-पैक्स उत्तरावतु, इब्राहिमपुर (बाराबंकी), हरदोई, गनीर कला, नगराम चौकी (लखनऊ) की समितियों के सचिवों को क्यूआर कोड प्रदान किए गए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सहकारिता सौरभ बाबू, आयुक्त एवं निबंधक योगेश कुमार, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक आलोक कुलश्रेष्ठ सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

40वें आयटो वार्षिक सम्मेलन में उत्तर प्रदेश पर्यटन मंडप बना आकर्षण का केंद्र

लखनऊ। ओडिशा के पुरी में 22 से 25 अगस्त 2025 तक आयोजित 40वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आयटो) वार्षिक सम्मेलन में उत्तर प्रदेश पर्यटन मंडप ने उपस्थित प्रतिनिधियों का ध्यान खींचा। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्य अतिथि के रूप में किया, जबकि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के स्टॉल का उद्घाटन ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने किया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस सम्मेलन में प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन आकर्षणों को प्रदर्शित किया गया। यूपी पर्यटन स्टॉल पर इस बार काशी-विश्वनाथ धाम (अयोध्या-काशी-प्रयागराज), दीपोत्सव और रंगोत्सव सहित भव्य धार्मिक आयोजनों की झलक पेश की गई। सम्मेलन में देशभर से 1,000 से अधिक प्रतिनिधि, टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायी और ट्रैवल मीडिया शामिल हुए। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आयटो सम्मेलन उत्तर प्रदेश के पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस मंच पर पर्यटन उद्योग के नेतृत्व और सरकारी हितधारक मिलकर इनबाउंड टूरिज्म के भविष्य और निवेश, नवाचार तथा तकनीकी सहयोग के अवसरों पर चर्चा कर रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन उत्तर प्रदेश पर्यटन मंडप आगंतुकों के लिए मुख्य आकर्षण बना। प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से इस पर्यटन में कोई दिखाई और कन्नौज की पारंपरिक इत्र निर्माण परंपरा को अनुभवात्मक उत्पाद के रूप में देखा। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नेटवर्किंग सत्रों में अयोध्या के राम मंदिर सर्किट, वाराणसी के विश्व धरोहर और बुंदेलखंड में इको-टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि आयटो के माध्यम से राज्य सरकार देश के अग्रणी टूर ऑपरेटर्स और उद्योग जगत के नेताओं से सीधे संवाद कर रही है। यह केवल प्रचार और व्यापारी के प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पर्यटन अवसंरचना का विस्तार, निजी निवेश को आकर्षित करना और अनुभवों का विविधीकरण भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन, इको-टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, एग्री टूरिज्म, क्रूज पर्यटन और एडवेंचर टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं, जो देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। सम्मेलन में पर्यटन महानिदेशक एवं अतिरिक्त सचिव भारत सरकार सुमन बिल्ला, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के चेयरमैन नीरज शर्मा और उत्तर प्रदेश पर्यटन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक प्रदेश को भारत का अग्रणी पर्यटन गंतव्य बनाया जाए, जहां आने वाला हर पर्यटक संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव लेकर लौटे।

राजकीय आईटीआई अलीगंज में रोजगार कैंपस ड्राइव: 22 युवाओं को मिला रोजगार

लखनऊ। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), अलीगंज, लखनऊ में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि. का कैम्पस ड्राइव सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आईटीआई के प्रधानाचार्य राज कुमार यादव ने कंपनी प्रतिनिधियों से अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन करने की अपील की और चयनित युवाओं को लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन एवं प्लेसमेंट ऑफिसर एस. ए. खान ने जानकारी दी कि इस कैम्पस ड्राइव में कुल 29 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 22 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के बाद चयन हुआ। चयनित युवाओं को कंपनी द्वारा प्रतिमाह 13,000 रुपये स्टाइपेण्ड प्रदान किया जाएगा। एस. ए. खान ने यह भी बताया कि रोजगार से वंचित अभ्यर्थी आगामी 30 अगस्त 2025 को आईटीआई अलीगंज में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक- श्रीमती पुष्पा शर्मा द्वारा बुद्धा प्रिन्टर्स, ज्योति नगर मधुकरपुर, निकट-हीरो होण्डा एजेन्सी, जनपद-सिद्धार्थनगर (उ0प्र0) 272207 से मुद्रित एवं प्रकाशित। सम्पादक- राजेश कुमार शर्मा
आर.एन.आई. न.-UPHIN/2012/49458 9415183471, 9453824459 दैनिक बुद्ध का संदेश 9795951917, 9415183471 @budhakasandesh budhakasandeshnews@gmail.com www.budhakasandesh.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट. के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद जनपद-सिद्धार्थनगर न्यायालय के अधीन ही मान्य होगा।

एमेजॉन एमएक्स प्लेयर ने हाफ सीए सीजन 2 का ट्रेलर किया रिलीज, किताबों से ज्यादा जिंदगी की सीख, 27 अगस्त से मुफ्त में होगी स्ट्रीम

नेहा मलिक के ग्लैमरस लुक्स ने फैंस को किया दीवाना, समुद्र किनारे फ्लॉन्ट किया बोल्ड अंदाज

बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की फिल्म कुली की पकड़ बरकरार, दुनियाभर में कमाए 429.75 करोड़ रुपये

वॉर 2 ने पार किया 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा, 8वें दिन हुई इतनी कमाई

अपनी लकजरी ब्रांड वाली सैंडल की ऐसे करें देखभाल, लंबे समय तक रहेंगी नए जैसी